चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आश्वासन

आईटीआई के बाद गीडा में होगी ट्रेनिंग, सरकार देगी आधा वेतन

उद्योग

- उद्यमियों की शिकायत टेक्निकल कोर्स के बाद भी उपयोगी नहीं हैं छात्र
- सीएम ने किया आश्वस्त, ट्रेनिंग अवधि के दौरान आधा वेतन सरकार देगी
- छह महीने की ट्रेनिंग के बाद स्थाई तौर पर रखे जा सकेंगे ट्रेनी

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। राजकीय और निजी क्षेत्र में जिले के 140 आईटीआई से विभिन्न ट्रेड से कोर्स कर निकलने वाले 10 हजार से अधिक बच्चों को लेकर उद्यमियों की शिकायत रहती है कि वे उनकी यूनिट की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों को भरोसा दिया है कि वह कोर्स करने वाले बच्चों को फैक्ट्रियों में तय अवधि के लिए ट्रेनिंग में रखें। इस दौरान आधे वेतन का इंतजाम सरकार करेगी। इसके साथ ही सीएम ने स्थानीय फैक्ट्रियों में जरूरत के हिसाब से तकनीकी कोर्स तैयार करने की बात भी कही है।

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह और पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल के नेतृत्व में उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था। जहां फैक्ट्रियों में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर चर्चा हुई। गीडा को लेकर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष आरएन सिंह ने समस्या गिनाते हुए कहा कि आईटीआई से लेकर पॉलिटेक्निक कोर्स करने वाले युवा फैक्ट्रियों की जरूरत के हिसाब से फिट नहीं होते हैं।

ऐसे में रोजगार मुहैया कराने में दिक्कत आती है। जिस पर सीएम ने कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को रोजगार दें। छह महीने या तय ट्रेनिंग अवधि में आधा वेतन सरकार मुहैया कराएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय फैक्ट्रियों के जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने की भी सलाह दी।

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल का कहना है कि रोजगार को लेकर यह कदम बेहद सराहनीय है। इससे फैक्ट्रियों को काबिल युवा मिलेंगे। ट्रेनिंग अवधि में वेतन का बोझ भी आधा रहेगा। गीडा से धुरियापार में शराब, सीमेंट, सरिया, ग्रीन एनर्जी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी संभावना है।

फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों के साथ चैंबर के पदाधिकारी बैठक कर पाठ्यक्रम को लेकर सुझाव देने को तैयार हैं।

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह का कहना है कि सीएम की पहल सराहनीय है। ट्रेनिंग अवधि में आधा वेतन सरकार के देने से उद्यमियों को सहूलियत होगी।

वर्तमान में बड़ी जरूरत सॉफ्टवेयर ऑपरेटरों की है। इसे लेकर प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार आसानी से मिलेगा। फैक्ट्रियों की जरूरत पर पाठ्यक्रम को लेकर उद्यमियों की जल्द ही बैठक होगी।

आईटीआई कर हर साल निकलते हैं 10 हजार छात्र: गोरखपुर जनपद में 10 राजकीय और निजी क्षेत्र में 130 आईटीआई हैं। विभिन्न पाठ्यक्रम में 10000 से अधिक छात्र दो वर्षीय कोर्स पूरा करते हैं। चरगांवा राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य संतोष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि पहले भी उद्यमियों के साथ बैठक कर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर चर्चा हुई थी। उद्यमियों की तरफ से सुझाव का स्वागत है। पाठ्यक्रम को लेकर सुझाव निदेशक को भेजा जाएगा।